# मोदी सरकार की 'फास्ट ट्रैक' कूटनीति (पड़ोसी देशों के विशेष संदर्भ में)

**अमित कुमार सिंह**
शोध छात्र (एस आर एफ)
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

Received Dec. 02, 2017 Accepted Jan. 01, 2018

**ABSTRACT** *वैश्विक अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाने की आकांक्षा रखने वाले देश के लिए एक दोस्ताना और शांतिपूर्ण पड़ोस का होना अतिमहत्वपूर्ण है। भारत एक उपमहाद्वीपीय आकार का देश है जो चारों तरफ से पड़ोसियों से घिरा हुआ है जिनका रवैया सदैव ही शत्रुतापूर्ण रहा है और उनमें मुख्य रूप से पाकिस्तान व चीन जैसे देश हैं, जिनसे भारत ने अतीत में युद्ध भी लड़े हैं। यही कारण है कि अपनी स्थापना के दिनों के बाद से ही स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की प्रमुख चुनौतियों में से एक अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की रही है। इसलिए भारत को एक क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरने की कुंजी नई दिल्ली के पास है और उसमें अपने पड़ोसियों के साथ नीतियों के स्तर पर कितना सामंजस्य बैठाने की क्षमता है उस पर निर्भर करता है खासकर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका।*

भारत की सुरक्षा को भारतीय उपमहाद्वीप की सुरक्षा से अलग नहीं किया जा सकता है। इसकी आर्थिक नियति अपने पड़ोसियों के जाल में फंसी हुई है। लगातार सरकार दर सरकार भारत का अपने पड़ोसियों से रिश्ता कुछ समयों के लिए और ज्यादातर संकट के मुताबिक बनता–बिगड़ता रहा है। लेकिन अब इसके बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने पूर्ववर्ती नेताओं के पड़ोसी देशों की कभी–कभी यात्रा करने की नीति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। वास्तव में पहला काम भारतीय उपमहाद्वीप के नेताओं से सम्पर्क स्थापित करने का होना चाहिए। मोदी सरकार के लिए अपने पड़ोसियों के साथ बिगड़े रिश्तों की तुरन्त मरम्मत जरूरी है। जहाँ हमारे द्विपक्षीय रिश्ते को तत्काल तवज्जो देने की मांग हो रही है। वही हमारा प्रत्येक द्विपक्षीय रिश्ता एक हद तक निराशा की गिरफ्त में है। प्रत्येक पड़ोसी की समृद्धि और उसके कल्याण में हमारा बड़ा दांव लगा है। हमें उन तक पहुंचने की जरूरत है हमें उनको इस हद तक तैयार करने की जरूरत है कि वो समझ सकें कि सहयोग केवल व्यक्तिगत, द्विपक्षीय और सामूहिक हित की जरूरत है बल्कि परिपक्वता और बुद्धि भी इसी की मांग करते हैं।

अगर मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को पुर्नजीवित कर और वृद्धि की गति को बढ़ाने के जरिये भारत के इतिहास को फिर से लिखना है तो उनकी सरकार को ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि भारत के पड़ोसी राजनीतिक तौर पर स्थिर और आर्थिक तौर पर मजबूत हैं। केवल एक स्थिर पड़ोसी भारत को उपमहाद्वीप के बाहर विस्तार कर अपनी छाप छोड़ने में मदद कर सकता है और उसके महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने संसद में दिए अपने एक प्रमुख अभिभाषण में इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों से शांतिपूर्ण और दोस्ताना रिश्ता चाहता है लेकिन अगर कहीं लड़ाई की जरूरत पड़ी तो उससे पीछे भी नहीं हटेगा। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि मेरी सरकार पूरी ऊर्जा के साथ चीन समेत अपने पड़ोसियों के साथ शामिल होगी जिनके साथ मिलकर हम अपनी रणनीतिक और सहयोगी साझीदारी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

मोदी के नेतृत्व वाली राजग–2 की सरकार ने 'पहले पड़ोस' नामक एक नई नीति बनाई है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसे भारत की 'बहुत स्पष्ट' प्राथमिकता मानती हैं और इसे मोदी की 'फास्ट ट्रैक' कूटनीति का एक हिस्सा बताती हैं। मात्रात्मक और तथ्यात्मक रूप में देखें तो भूटान से लेकर अमेरिका तक मोदी की विदेश यात्राओं की संख्या नई दिल्ली में नई सरकार द्वारा निर्धारित 'फास्ट ट्रैक' कूटनीति की प्रकृति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को यह दिखाने के लिए चुना कि भारत अपने पड़ोसियों को कितना अधिक महत्व देता है, भले ही वे कितने छोटे और कमजोर क्यों न हों? मोदी ने उसके बाद नेपाल का दौरा किया। सत्ता में आने के ढाई महीने के भीतर किसी दक्षिण एशियाई पड़ोसी यानि नेपाल का दौरा करने के उनके फैसले को महज एक संयोग के रूप में नहीं देखा गया। ऐसा लंबी अवधि के लाभ के उद्देश्य से चीन के पक्ष में खतरनाक तीरके से नेपाल के झुकाव को रोकने के लिए किया गया था। विभिन्न विवादास्पद द्विपक्षीय मुद्दों पर नेपाल और भूटान के नेतृत्व से मोदी ने जिस तरह बातचीत की, समझौतों

पर हस्ताक्षर किए और उनके साथ सहमति बनाई उससे भारत के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उत्तरी पड़ोसियों के साथ संबंधों को तेज गति से आकार देने की उनकी भावना का पता चलता है।

सितम्बर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के मौके पर बांग्लादेश और नेपाल के अपने समकक्षों तथा श्रीलंका के राष्ट्रपति से साथ अलग से द्विपक्षीय बैठकें की। उन्होंने उनके साथ आतंकवाद और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार जैसे साझा मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। सभी नेताओं ने सार्क को एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। 'योग' को बढ़ावा देने के लिए मोदी की पहल पर एक 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के लिए उन्होंने अपना हार्दिक समर्थन और पूर्ण सहयोग देने का वादा किया। तीनों नेताओं ने भी अपने–अपने देशों की यात्रा के लिए भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों से एक सार्क उपग्रह विकसित करने का आग्रह किया ताकि उस उपग्रह को भारत अपने पड़ोसियों को उपहार में दे सकें। यह मोदी के उस सपने का हिस्सा है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से भारत को मिलने वाले लाभ को सार्क के सदस्यों के साथ साझा किया जायेगा। उनकी दृष्टि में इससे पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे, क्योंकि यह विशेष रूप से गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए सार्क देशों की जरूरतों को पूरा करेगा। भारत दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जिसने अत्याधुनिक अंतरिक्षयान का निर्माण और प्रक्षेपण किया है जो संचार और प्रसारण, मौसम निगरानी, धरती के परतों का अध्ययन, नेविगेशन के साथ–साथ वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी उपयोगी है। इसलिए मोदी ने बहुत स्पष्टता से कहा है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मानवता की सेवा के लिए है, न कि इसका उद्देश्य ताकतवर बनना है।

हाल के दिनों में पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को लेकर भारत ने अतिरिक्त प्रयत्न किया है। भूटान को यह अहसास कराया जा रहा है कि भारत उसे एक खास दोस्त के रूप में देखता है; तथा नेपाल के साथ समानता और प्राथमिकता के आधार पर व्यवहार किया जा रहा है।

निकट पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों में जुड़े नए अध्याय के कुछ अच्छे लक्षणों के बावजूद, इस दिशा में बाधाओं के रूप में अनेक चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं। पाकिस्तान के साथ कश्मीर और सीमापार आतंकवाद, श्रीलंका के साथ जातीय तमिलों के अधिकार व पुनर्वास तथा मछुआरों द्वारा सीमा का उल्लंघन, नेपाल के साथ सीमांकन, 1950 की संधि की पुनर्व्याख्या, उसके आंतरिक मामलों और पारगमन अधिकार में भारत का हस्तक्षेप, बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते पर सहमति, तीस्ता जल बंटवारा, सीमा प्रबंधन, अवैध आव्रजन और अवैध दवाओं तथा हथियारों की तस्करी, भूटान के साथ पारगमन अधिकार, सांस्कृतिक सुरक्षा और संप्रभुता का मुद्दा, और मालदीव के साथ जीएमआर अनुबंध रद् करने और निवेश असुरक्षा का मुद्दा–ऐसे अनेक चुनौतियों से पार पाना अभी बाकी है।

दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए भारत के प्रयासों के बावजूद, पाकिस्तान से दोस्ताना रिश्ते कायम करना भारत की विदेश नीति का एकमात्र चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। ऐसा माना जाता है कि एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की वैधता भारत विरोधी बयानबाजी पर निर्भर करती है और वहाँ के लोगों में भारत केन्द्रित किसी संकट के दौरान इस्लामाबाद सरकार के समर्थन देने की आदत है।

सुरक्षा और आर्थिक एकजुटता, क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क एनडीए सरकार के प्रमुख मुद्दे हैं। बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय सहयोग को नई ऊर्जा से आगे बढ़ाने की संभावना है और दक्षिण एशिया के साथ रिश्तों में ये प्रमुख विशेषता के तौर पर उभरेगा। इस लिहाज से मोदी का सार्क देशों के नेताओं को निमंत्रण सही मायने में एक खोज है और पड़ोसियों के साथ सरकार के नये नजरिये की तरफ इशारा करता है कि वो इस इलाके में भारत के लिए उल्लेखनीय साझीदार बने रहेंगे। मोदी ने अपने पड़ोसियों के संदर्भ में बहुपरत दृष्टिकोण का समर्थन किया है। चीन के मामले में वर्तमान शासन ने एक तरफ आर्थिक संबंधों के माध्यम से एक सहयोगी प्रतिस्पर्धी माहौल का पालन किया है और दूसरी तरफ बाहरी शक्तियों के साथ सहयोग के जरिये चीनी मुखरता के प्रभाव को दबाने का प्रयास भी किया है। पाकिस्तान के साथ मुख्य जोर सदभावना और विश्वास के निर्माण पर है। मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने पड़ोस में शांति और स्थायित्व की है जिससे कि भारत जब अगले दशक तक एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर लोगों का ध्यान खींचने के साथ ही नेतृत्व हासिल करना भी महत्वपूर्ण होगा।

**Reference :**

1. Jha, Nalinikanta (2003). Domestic Conflicts in Nepal Origin, Challenges and Prospects' in Mahavir Singh (ed.) Asia Annual-2003, Delhi: Sipra Publications, p. 203.

2. Raja Mohan, C. (2000). Indian and its extended neighbourhood. The Hindu, 8 June.
3. Scott, David (2009). India's "Extended Neighbourhood" Concept: Power Projectioni for a Rising Power. India Review, 8:2, pp. 107-143.
4. Zhao, S (2008). China Rising in Suisheng Zhao (ed.) 'China-US Relations Trnasformed Perspectives and Strategic Interactions', Oxon, Routledge, p. 37.
5. See BJP election manifesto of 2014. pp. 39-40.
6. Saran, Shyam (2014), "India's External Relations: What the Modi Factor Promises", S. Rajaratnam School of Internatinoal Studies (RSIS) Commentaries, p.1-2.
7. Hardeep Singh Puri, "Foreign Policy challenges for the new Government", 9 May 2014, URL:http://hardeepsinghpuri.com/foreign-policy-challenges-for-the-new-government/
8. Hussain, Wasbir "India and Its Neighbourhood: Foreign Policy Challenges for Modi", Center for Development and Peace Studies (CDPS), 23 May 2014, p.1
9. Khan, Iqbal "Peaceful neighbourhood: A pipedream", Pakistan Observer, 04 June 2014, URL:http://pakobserver.net/detailnews.asp?id=243479
10. Pandey, Vikas "Can India's Modi intergrate South Asia?, BBC NEWS India, 29 May 2014, p.1-2